

उत्तर प्रदेश में कृषिव्यवसाय परियोजना शुरू की जाएगी

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से [वशिव बैंक](#) द्वारा वित्त पोषित 4,000 करोड़ रुपए की कृषिव्यवसाय और उद्यमिता परियोजना शुरू करने की तैयारी कर रही है।

मुख्य बंदि

- इस पहल से पूरवी उत्तर प्रदेश और [बुंदेलखंड कषेत्र](#) के 28 ज़िलों के कसिनों, कृषिसमूहों तथा कृषि [सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों \(MSME\)](#) को लाभ होगा।
- अनुमान है कि इस परियोजना से दस लाख कसिनों को लाभ मलिंगा, जनिमें कृषि [स्वयं सहायता समूहों \(SHG\)](#) से जुड़ी 30% ग्रामीण महलियाँ भी शामिल हैं।
 - परियोजना के तहत 100,000 मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी
 - इसके अतरिकित, 500 कसिनों को उन्नत कृषि तकनीकों के प्रशिक्षण के लिये अंतरराष्ट्रीय दौरों पर भेजा जाएगा।
- सरकार [उच्च उपज देने वाली बीज कसिमों](#) और कृषि बुनियादी ढाँचे में नविश करने, कृषि कषेत्र के लिये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म वकिसति करने तथा कसिनों की आय बढ़ाने के लिये [कार्बन क्रेडिट बाज़ार](#) का लाभ उठाने में उनकी सहायता करने की आशा रखती है।

कार्बन बाज़ार

- **कार्बन बाज़ार मूलतः कार्बन उत्सर्जन पर मूल्य निर्धारण करने का एक साधन है** - वे व्यापार प्रणालियाँ स्थापति करते हैं जहाँ कार्बन क्रेडिट या अनुमतियाँ खरीदी और बेची जा सकती हैं।
 - कार्बन क्रेडिट एक प्रकार का **व्यापार योग्य परमिट** है, जो [संयुक्त राष्ट्र](#) के मानकों के अनुसार, वायुमंडल से **एक टन कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने**, कम करने या पृथक करने के बराबर होता है।
 - इस बीच, कार्बन अनुमतियाँ या सीमाएँ, **देशों या सरकारों द्वारा** उनके उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के अनुसार **निरधारति** की जाती हैं।
 - कार्बन ट्रेडिंग की औपचारिक शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के [क्योटो प्रोटोकॉल](#) के तहत वर्ष 1997 में हुई थी।